Homeless persons in the country

2652. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of homeless persons in the country during the last five years Statewise; and

(b) the number of homeless persons in cosmopolitan cities of Delhi, Bombay, Madras and Calcutta during 1990-91?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The number of homeless persons in the country during the last five years is not available. However, the number of houseless persons state-wise according to the 1981 Census is given in the Statement enclosed. *(See* below)

(b) The number of homeless persons in cosmopolitan cities of Delhi, Bombay, Madras and Calcutta during 1990-91 is not available. The number of homeless persons in these cities | urban agglomeration according to 1981 Census is given in the Statement at Annexure-II.

Statement

State-wise Number of Houseless persons in India according to the 1981 *Census.*

In dia	a/State/Union Territory	Houseless population for 1981 Census	India/State/Union Territory	Houseless population for 1981 Census
	INDTA*%	2;342,954		
1.	Andhra Pradesh	250,866	12. Manipur	128
2.	Assam	N.A.	13. Meghalaya	335
3.	Bihar	60,184	14. Nagaland	258
4.	Gujarat	310.414	15. Orissa .	50,761
5.	Haryana	43.698	16. Punjab .	56,3 72
6.	Himachal Pradesh	23,929	17. Rajasthan	166,815
7.	Jammu & Kashmir .	10,792	18. Sikkim .	1,306
8.	Karnataka	127,750	19. Tamil Nadu .	57,461
9.	Kerala	21,746	20. Tripura	489
10.	Madhya Pradesh	332,437	21. Uttar Pradesh.	108,540
11.	Maharashtra		22. West Bengal .	132,802
1.	*UNION TERRITIORIES* A & NIslands	542,457		
		178		
2.	Arunachal Pradesh .	4,047		
3.	Chandigarh	1,025		
4.	D & N Haveli .			
5.	Delhi . Goa,	26,870		
6.	Daman & Diu .	7,198		
7.	Lakshadweep .	3		
8.	Mizoram	375		
9.	Pondicherry	3,798		

*Excludes Assam where census could not be held owing to disturbed conditions prevailing there at the time of 1981 Census.

*Excludes Population of areas under unlawful occupation of Pakistan and China where census could not be taken.

Annexure—II

Houseless Population in cosmopollitan cities as per 1981 *Census*

Name of City/Urban Agglomeration	Houseless Population for 1981 Census
1. Delhi UA	22,513
2. Greater Bombay	44,289
3. Madras UA	8,140
4. Calcutta UA	64,385

उत्तर प्रदेश की शहरी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

2653. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई कुछ शहरी विकास परियोजनाएं स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से सात नगरों नामत: (1) कोसी कलां (2) सिकंदराबाद (3) बिलासपुर (4) मौरानीपुर, (5) चिनार (6) मवाना (7) देवबंद के संबंध में परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । चालू वित्त वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनन्तिम रूप से पांच नगरों का नियतन किया गया है और स्वीकृति समिति ने दिनांक 27 फरवरी, 1992 को हुई अपनी बैठक में प्रथम दो नगरों अर्थात् कोसी कलां और सिकंदराबाद की परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की हैं और प्राथमिकता क्रम में बिलासपुर, मौरानीपुर और चिनार नामक शेष तीन नगरों के संबंध में स्वीकृति समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश में गंदी बस्तियों की दशा

2654. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गंदी बस्तियों की दशा को सुधारने के लिए विशेष सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को गंदी बस्तियों का सुधार करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां, वाराणसी और आगरा में मलिन बस्तियों के उन्नयन के लिए ओवरसीज डवलेपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ डी ए-यू के) से सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से क्रमश: अक्तूबर, 1990 और जुलाई, 1991 में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । मलिन बस्ती निवासियों के जीवनस्तर को ऊंचा करने के लिए अवसंरचना के भौतिक विकास, जन सुविधाओं के प्रावधान, स्वास्थ्य देखभाल सामुदायिक विकास आदि पर दोनों प्रस्तावों में विचार किया गया है ।